



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

• 466] नई दिल्ली, सोमवार, सितम्बर 30, 1985/आश्विन 8, 1907
No. 466] NEW DELHI, MONDAY, SEPTEMBER 30, 1985/ASVINA 8, 1907

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate
compilation

उद्योग एवं कम्पनी कार्य मंत्रालय

(औद्योगिक विकास विभाग)

नई दिल्ली, 30 सितम्बर, 1985

आदेश

क्र. प्रा. 716 (अ)/18कक/आई डी. प्रार ए/85 — केन्द्रीय सरकार
उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65)
द्वारा 18कक की धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते
हुए भारत सरकार के उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) के
अ. सं. का. प्रा. 874 (अ)/18कक/आई डी. प्रार ए/80, तारीख
नवम्बर, 1980 द्वारा (जिसे इसमें इसके पश्चात्, उक्त आदेश कहा
है) बिहार राज्य में मोतीपुर शूगर फैक्ट्री लिमिटेड, मोतीपुर,
मुजफ्फरपुर नामक औद्योगिक उपक्रम (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त,
उद्योगिक उपक्रम कहा गया है) का प्रबंध, 2 नवम्बर, 1982 तक की,
यह तारीख भी सम्मिलित है, दो वर्ष की अवधि के लिए
स्टेड शूगर कार्पोरेशन लिमिटेड, पटना द्वारा ग्रहण किए जाने
वाले प्राधिकृत किया जा,

: केन्द्रीय सरकार ने भारत सरकार के उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक
विभाग) के आदेश सं. 769 (अ)/18कक/आई डी. प्रार ए/
तारीख 30 अक्टूबर, 1982 द्वारा उक्त अवधि को 2 नवम्बर,

1983 तक, जिसमें यह तारीख भी सम्मिलित है, एक वर्ष तक के लिए
बढ़ा दिया जा,

और कलकत्ता उच्च न्यायालय ने, तारीख 29 सितम्बर, 1983 को
अपने आदेश द्वारा यह निदेश दिया था कि केन्द्रीय सरकार उक्त औद्योगिक
उपक्रम के प्रबंध ग्रहण की अवधि को, 2 नवम्बर, 1983 से परे और
नहीं बढ़ाएगी, और उक्त औद्योगिक उपक्रम बिहार स्टेड शूगर कार्पोरेशन
लिमिटेड, पटना के प्रबंधाधीन तब तक बना रहेगा जब तक कि
रिट को अर्जों का निपटान नहीं हो जाता;

और, उक्त उच्च न्यायालय ने तारीख, 23 अप्रैल, 1984 के अपने
आदेश द्वारा केन्द्रीय सरकार को यह निदेश दिया था कि, वह उक्त
औद्योगिक उपक्रम और उसके निदेशकों को प्रस्तावित आदेश के बिना
कारण बताने के लिए उचित अवसर प्रदान करने के पश्चात्, उक्त औद्योगिक
उपक्रम के प्रबंध ग्रहण की अवधि को बढ़ा सकती है,

और, केन्द्रीय सरकार ने उक्त उच्च न्यायालय के उक्त निदेशों का
अनुपालन करते भारत सरकार के उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास
विभाग) के आदेश सं. का. प्रा. 393 (अ)/18कक/आई डी. प्रार ए/
84 तारीख, 19 मई, 1984 और का. प्रा. 813 (अ)/18कक/आई डी.
प्रार ए/84, तारीख 30 अक्टूबर, 1984 द्वारा उक्त अवधि को अक्टूबर
समय पर 30 सितम्बर, 1985 तक जिसमें यह तारीख भी सम्मिलित
है, बढ़ा दिया जा ;

और उक्त औद्योगिक उपक्रम तथा उसके निदेशकों को एक नई सुचना दी गई है जिसमें प्रबंध प्रबंधकों बढ़ाए जाने के सरकार के आशय को प्रभावित किया गया है और उन को यह कारण बनाने का निदेश दिया गया है कि उक्त प्रबंधकों को क्या नहीं बढ़ा दिया जाए,

और उक्त औद्योगिक उपक्रम द्वारा या उसके निदेशकों द्वारा कोई कारण नहीं बताया गया है,

और केन्द्र सरकार की यह राय है कि लोकहित में यह अनिवार्य है कि उक्त औद्योगिक उपक्रम, बिहार शूगर कारपोरेशन लिमिटेड, पटना के प्रबंध के अधीन 30 जून 1986 तक की, जिसमें यह तारीख को सम्मिलित है, और प्रबंध के लिए बना रहे,

धारा : अब, केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 18AA की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह निदेश देता है कि उक्त आदेश 30 जून, 1986 तक की, जिसमें यह तारीख को सम्मिलित है, और प्रबंध के लिए प्रभावी बना रहेगा।

[फा. सं. 4(13)/80 सं. गू. एस.]

ए. पी. सरवान, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF INDUSTRY AND COMPANY AFFAIRS

(Department of Industrial Development)

New Delhi, the 30th September, 1985

ORDER

S.O. 716(E)|18AA|IDRA|85.—Whereas by the Order of the Government of India in the Ministry of Industry (Department of Industrial Development) No. S.O. 874(E)|18AA|IDRA|80, dated the 3rd November, 1980 (hereinafter referred to as the said Order), the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 18AA of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), authorised the Bihar State Sugar Corporation Limited, Patna, to take over the management of the Motipur Sugar Factory Limited, Motipur, District Muzaffarpur in the State of Bihar (hereinafter referred to as the said industrial undertaking) for a period of two years up to and inclusive of the 2nd November, 1982;

And, whereas, the Central Government by order of the Government of India in the Ministry of Industry (Department of Industrial Development) No. S.O. 769(E)|18AA|IDRA|82, dated the 30th October, 1982, extended the said period by one year up to and inclusive of the 2nd November, 1983;

And, whereas, the High Court at Calcutta had, vide its order dated the 29th September, 1983, directed that the Central Government shall not make any further extension of the take over of the management of the said industrial undertaking beyond the 2nd November, 1983, and that the said industrial undertaking shall continue to be under the management of the Bihar State Sugar Corporation Limited, Patna till the disposal of the writ petition;

And, whereas, the said High Court had, vide its order dated the 23rd April, 1984, directed the Central Government to extend, after giving the said industrial undertaking and its directors a reasonable opportunity of showing cause against the proposed order, the period of take over of the management of the said industrial undertaking;

And, whereas, while complying with the said direction of the said High Court, the Central Government by the orders of the Government of India in the Ministry of Industry (Department of Industrial Development) No. S.O. 393(E)|18AA|IDRA|84 dated the 19th May, 1984 and S.O. 813(E)|18AA|IDRA|84, dated the 30th October, 1984, extended from time to time the said period up to and inclusive of the 30th September, 1985;

And, whereas, a fresh notice has been given to the said industrial undertaking and its directors intimating the Government's intention to extend the said period directing them to show cause why the said period should not be extended;

And, whereas, no cause has been shown either by the said industrial undertaking or by its directors;

And, whereas, the Central Government is of the opinion that it is expedient in the public interest that the said industrial undertaking should continue under the management of the Bihar State Sugar Corporation Limited, Patna, for a further period up to and inclusive of the 30th June, 1986;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 18AA of the said Act the Central Government hereby directs that the said order shall continue to have effect for a further period up to and inclusive of the 30th June, 1986

[File No. 4(13)|80-CL

A. P. SARWAN, Jt. Sec